CASE STUDY- 06

आप प्रदेश के लोक निर्माण विभाग में एक वरिष्ठ अधिकारी है, जिसके कारण सरकार के निर्णयों एवं गोपनीय सूचनाओं की जानकारी आपको पहले ही मिल जाती है। सरकार ने वर्तमान में अवसंरचना के विकास के लिये कुछ ऐसे निर्णय लिये है, जिनकी जानकारी यदि अवसंरचना के विकास में लगी कम्पनियों को लग जाये तो वे बड़ा लाभ कमा सकती हैं। इन कम्पनियों में से एक ऐसी है, जिसने पूर्व में सरकार के लिए काफी अच्छा एवं गुणवत्तायुक्त कार्य किया है तथा इस कम्पनी का मालिक विभाग के मंत्री का घनिष्ठ है। मंत्री ने उस सूचना को अपने घनिष्ठ को देने का संकेत आपको दिया है। ऐसी स्थिति में-

(i) ***आपके पास क्या-क्या विकल्प उपलब्ध हैं?***

(ii) ***प्रत्येक विकल्प का परीक्षण करके बताइए कि आप कौन-सा विकल्प चुनेंगे? कारण बताइए।***

(250 शब्द, 20 अंक)

उत्तर: **उपर्युक्त मामले का गहनता से अध्ययन करने पर यह स्पष्ट होता है कि इसमें चार मुख्य पक्षकार हैं-**

	पक्षकार		**संबंधित नैतिक चिंता**
(i)	मैं स्वयं (अधिकारी की भूमिका)	—	सत्यनिष्ठा, गोपनीयता
(ii)	अन्य कंपनियाँ	—	निष्पक्ष प्रतिस्पर्द्धा, समान अवसर
(iii)	सरकार	—	निष्पक्ष प्रतिस्पर्द्धा को बढ़ावा, सबको व्यापार का समान अवसर
(iv)	लोक निर्माण विभाग के मंत्री	—	भाई-भतीजावाद, गोपनीयता का उल्लंघन

उपरोक्त स्थिति में मेरे सामने निम्नलिखित विकल्प उपलब्ध होंगे-

(i) मंत्री के संकेत को समझकर कंपनी के मालिक को सूचित कर देना।

(ii) मंत्री के संकेतों को अनसुनाकर अपने निर्धारित कर्त्तव्य एवं प्रक्रिया को पूरा करना।

(iii) अवसंरचना के विकास में लगी सभी कंपनियों को सही समय पर सरकार के आदेशानुसार विज्ञप्ति जारी करके सूचित करना।

पहला विकल्प:

- **फायदा:** विभागीय मंत्री खुश रहेंगे और उनका विश्वासपात्र बनने का अवसर मिलेगा।
- **घाटा:** सत्यनिष्ठा और गोपनीयता का उल्लंघन होगा। प्राकृतिक न्याय के विपरीत होगा तथा भविष्य में इसी प्रकार का और कार्य करने की विवशता बढ़ेगी।

दूसरा विकल्प:

- **फायदा:** सत्यनिष्ठा की रक्षा होगी, सभी कंपनियों को समान अवसर मिलेगा।
- **घाटा:** मंत्री की नाराजगी बढ़ सकती है।

तीसरा विकल्प:

- **फायदा:** सरकार की छवि अच्छी बनेगी, क्रोनी कैपिटलिज्म का आरोप नहीं लगेगा। इससे भविष्य में सरकारी निर्णयों के दुरूपयोग करने वाले हतोत्साहित होंगे।

विभिन्न विकल्पों में से मैं दूसरे और तीसरे विकल्प को वरीयता दूंगा। इससे प्रशासन में पारदर्शिता बढ़ेगी और संशय का वातावरण हटेगा, भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी।

यहाँ इस बात की संभावना प्रबल बनी रहेगी की अच्छा और गुणवत्तापूर्ण कार्य करने वाली कंपनी को स्वत: ही प्रक्रिया के तहत जानकारी मिल जायेगी और वह उसका लाभ भी उठाएगी। ऐसी स्थिति में मंत्री जी की नाराजगी का भी प्रश्न उभरकर सामने नहीं आएगा। साथ ही अपनी और संगठन की सत्यनिष्ठा भी सुरक्षित बनी रहेगी।

KGS : 5th Floor, A13A, Graphix 1 Tower B, Sector 62, Noida, Uttar Pradesh-201309
Ph. No. : 8757354880